



- वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के निर्यात में पहली तिमाही में सैंतालीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- उन्चासीवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज निवास में एट होम समारोह का आयोजन किया गया।
- केन्द्र सरकार ने जी एस टी की संशोधित व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है।
- द्वीपसमूह में भारी वर्षा होने की संभावना।



वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निर्यात में 2025-26 की पहली तिमाही में 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के कारण 2014-15 से लेकर अब तक इस एक दशक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 31 बिलियन डॉलर से 133 बिलियन डॉलर तक की तीव्र वृद्धि हुई है।

श्री गोयल ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में भारत में दो मोबाइल विनिर्माण इकाईयां थीं। ये इकाईयां आज बढ़कर तीन सौ से अधिक हो चुकी हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत मोबाइल आयातक से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माता बन चुका है। यह इस यात्रा के सबसे बड़े परिवर्तनों में से एक है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में सौर मॉड्यूल, नेटवर्किंग उपकरण और चार्जर अडाप्टर्स से व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। निर्यात को सशक्त बनाने में इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।



द्वीपसमूह के उपराज्यपाल और द्वीप विकास एंजेसी के उपाध्यक्ष ने उन्चासीवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज निवास में एट होम समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल ने आमंत्रित अतिथियों से बातचीत की और उन्हें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में द्वीपसमूह की प्रथम महिला श्रीमती चित्रा जोशी भी उपस्थित थी। इस स्वागत समारोह में सांसद बिष्णू पद रे, मुख्य सचिव

डॉ चन्द्र भूषण, रक्षा और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा जन प्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाले लोग भी उपस्थिति थे। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जिन्होंने द्वीपसमूह में अपनी समर्पित सेवा प्रदान की।



श्री विजयपुरम स्थित नेताजी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर उपराज्यपाल ने ओलंपिक शैली की तीन फिटनेस मशालें प्रज्वलित कीं। ये मशालें ओलंपिक मूल्यों—उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान—का प्रतीक हैं। इन्हीं मशालों के माध्यम से फिट इंडिया अंडमान—निकोबार खेल महोत्सव की शुरुआत हुई और राष्ट्रीय खेल दिवस दो हजार पच्चीस के लिए द्वीपसमूह के समारोहों का आधिकारिक शुभारंभ किया गया। प्रत्येक मशाल द्वीपसमूह के तीन जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक उत्कृष्ट खिलाड़ी को सौंपी गई। निकोबार से आनंद लॉसन, दक्षिण अंडमान से प्राची टोप्पो और उत्तर—मध्य अंडमान से रेजिना कीरो को यह दायित्व दिया गया कि वे द्वीपों में मशाल यात्रा के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहित करें।



सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय ने वन विभाग और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय और परामर्श से नॉर्थ सिंक द्वीप में पर्यटन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है। इस एस ओ पी का प्रथमिक उद्देश्य नॉर्थ सिंक द्वीप में पर्यटन गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करना है। साथ ही इसकी अनूठी जैवविधता के संरक्षण और द्वीप के प्राकृतिक पर्यवरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह एस ओ पी जिम्मेदार पर्यटन, आंगतुक सुरक्षा, पर्यवरण संरक्षण, पोत संचालन आदि के लिए विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करता है। यह एस ओ पी पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है।



केन्द्र सरकार ने माल एवं सेवा कर जी एस टी की संशोधित व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। सरकार ने इस नए ढांचे में पांच फीसदी, अटठारह फीसदी वाली सिर्फ दो टैक्स दरों का ही प्रस्ताव रखा है जबकि लकज़री और हानिकारक वस्तुओं पर चालीस फीसदी टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। इसे दिवाली तक लागू हो जाने का अनुमान है। केन्द्र सरकार ने इस साल दिवाली तक मौजूदा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की जगह लेने के लिए संशोधित प्रारूप में दो स्लैब वाली जी एस टी दर संरचना और कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए विशेष टैक्स की दरों का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्रालय ने जी एस टी की दरों को युक्ति

संगत बनाने के लिए गठित राज्यों की वित्त मंत्रियों के समूह को अपना ये प्रस्ताव भेजा है। इसमें बारह और अट्ठाईस फीसदी की मौजूदा कर दरों को हटा दिया गया है। इसके अलावा जी एम ओ को भेजे प्रस्ताव में लकड़ी और हानिकारक वस्तुओं पर चालीस फीसदी तक विशेष टैक्स लगाने की तैयारी है।



भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव—जन्माष्टमी कल श्री विजयपुरम में उत्साह और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। मंदिरों में भजन गायन से लेकर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हुए। सभी मंदिरों को रोशनी से सजाये गये।



कल से द्वीपसमूह के सभी स्थानों पर भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार द्वीप समूह में एक या दो स्थानों पर तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश तथा गरज के साथ तूफ़ान आने और एक या दो स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। इस बीच हवा की गति 35 से 45 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार तक हो सकती है और समुद्र में हवा गति 55 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से चलने की संभावना है। स्थिति खराब होने के चलते मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे कल तक समुद्र में न जाएँ। तटीय स्थानों पर चेतावनी संख्या 3 जारी कर दी गई है।



जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार मौजूदा खराब मौसम की स्थिति के कारण, मुख्यभूमि, अंतर-द्वीपीय तथा तटीय क्षेत्र के जहाजों को बहुत कम समय में निलंबित या रद्द किया जा सकता है। इसी प्रकार, चाथम, बम्बूफ्लाट, डंडास पॉइंट, होपटाउन, फीनिक्स बे और बाहरी स्टेशनों के बीच फेरी सेवाओं का संचालन भी मौसम की स्थिति के आधार पर, कम समय में बाधित या निलंबित हो सकता है। सभी यात्रियों और पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना मौसम को देखते हुए बनाएं। किसी भी जानकारी के लिए यात्री फीनिक्स बे स्थित सूचना काउंटर से संपर्क कर या फ़ोन: 03192 – 245555 / 232714 में कॉल कर प्राप्त कर सकते हैं।



प्रशासन चाथम कॉजवे के नवीनीकरण पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इस परियोजना के कुछ महीनों में शुरू होने की संभावना है। अंडमान निकोबार प्रशासन ने केंद्रीय वित्त पोषण के तहत एक नए चाथम कॉजवे की शीघ्र मंजूरी और कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से हस्तक्षेप का भी अनुरोध किया है।

एन एच आई डी सी एल को अंडमान मरीन ड्राइव रोड के साथ-साथ नए चाथम कॉजवे के निर्माण का कार्य सौंपा गया है। लोगों की सुविधा के लिए कॉजवे के नवीनीकरण के लिए सभी संभव उपाय युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं।



युवा मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत माय भारत ने ज्ञान को साझा करने, क्षमता निर्माण और युवाओं के बीच नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन अगले महीने से लागू होगा। इसका उद्देश्य शासन, लोक नीति, सामाजिक उद्यमिता, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और अन्य क्षेत्रों में संयुक्त कार्यक्रम के माध्यम से समूचे देश में अट्ठारह से उनतीस वर्ष की आयु के एक लाख युवाओं को तैयार करना है।

